

वित्त लेखे, संघ सरकार  
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

भारत सरकार लेखा मानक: 3

INDIAN GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD: 3

सं.3 – संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिम राशियों का विवरण  
No. 3 – STATEMENT OF LOANS AND ADVANCES MADE BY THE UNION GOVERNMENT

भाग: 1 ऋणों और अग्रिम राशियों का सारांश : ऋणी समूहवार

Section: 1 Summary of Loans and Advances: Loanee group wise

ऋणी समूह	01 अप्रैल, 2020 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान चुकोती	अप्रतिसंहरणीय कर्ज और अग्रिम को बट्टे खाते डालना	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (2-6)	बकायों में ब्याज अदायगी
Loanee Group	Balance on April 1, 2020	Disbursements during the year	Repayments during the year	Write-off of irrecoverable loans and advances	Balance on March 31, 2021 (2+3)-(4+5)	Net increase/ decrease during the year (2-6)	Interest payment in arrears
1	2	3	4	5	6	7	8
							(लाख रुपयों में)
							(In lakhs of rupees)
राज्य सरकारें							
State Governments	17651412.90	14880393.36	1606327.78	–	30925478.48	–13274065.58	176872.33
संघ राज्य क्षेत्र सरकारें							
Union Territory Governments	430004.34	–	4371.43	–	425632.91	4371.43	249251.08
विदेशी सरकारें							
Foreign Governments	1422777.49	53915.11	31072.42	–	1445620.18	–22842.69	–
सरकारी निगम, गैर-सरकारी संस्थाएँ, स्थानीय निधियाँ, किसान आदि							
Government Corporations, Non-Government Institutions, Local Funds, Cultivators etc.	14324657.41	10035617.19	1340097.35	–	23020177.25	–8695519.84	3804539.25
सरकारी कर्मचारी							
Government Servants	18282.94 *0.03	14628.85	10447.52	–	22464.30	–4181.33	–
<b>जोड़ TOTAL</b>	<b>33847135.08</b> <b>0.03</b>	<b>24984554.51</b>	<b>2992316.50</b>	<b>–</b>	<b>55839373.12</b>	<b>–21992238.01</b>	<b>4230662.66</b>

टिप्पणियाँ :

Notes: -

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को कर्ज के रूप में अदा की गई ₹14880393.36 लाख की कुल राशि में से, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों में अंतर पूरा करने के लिए मंजूर किया गया कर्ज शून्य राशि था।  
Out of total amount of ₹14880393.36 lakh paid as loans to State/Union Territory Governments, Nil loans has been granted to cover gaps in resources of the State/Union Territory Governments.

2. 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ₹ 233459.91 लाख की पुनर्भदायगी 31 मार्च, 2021 तक बट्टे खाते डाल दी गई है।  
In pursuance of the recommendations of the 13th Finance Commission, repayments by the States/Union Territories amounting to ₹ 233459.91 lakh has been written off up to March 31, 2021.
3. वर्ष के प्रारंभ में, राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम के रूप में स्वीकृत कोई राशि शेष नहीं थी। वर्ष के दौरान, राज्य सरकारों का भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट के समाशोधन/परिहार के लिए अर्थोपाय अग्रिम के रूप में शून्य राशि का भुगतान किया गया था जिससे शून्य राशि शेष रही।  
At the beginning of the year, there was no balance of sanctioned amount to State Governments as Ways and Means Advances. During the year, Nil amount was paid as Ways and Means Advances to State Government for clearance/avoidance of overdrafts from the Reserve Bank of India leaving a balance of Nil amount.
4. “शाश्वत कर्ज” के रूप में मंजूर किए गए कर्ज के मामले निम्नलिखित हैं:—  
Following are the cases of loan having been sanctioned as “loan in perpetuity”

क्रम संख्या S. No.	ऋणी संस्था Loanee Entity	स्वीकृति वर्ष Year of Sanction	मंजूरी आदेश सं. Sanction Order No.	राशि Amount	(लाख रुपयों में) (In lakh of rupees) ब्याज दर Rate of Interest
1.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार State/Union Territory Government	—	—	—	—
2.	अन्य ऋणी संस्थाएं – Other loanee entities –				
	(i) भारत संचार निगम लिमिटेड Bharat Sanchar Nigam Limited	2003-04	25-1/2001-एसएटी/पीपी(पीटी) दिनांक 13.01.2003 25-1/2001-SAT/pp(pt) Dated 13.01.2003	72000.00	#
	(ii) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. Hindustan Shipyard Ltd.	2010-11	8(2)/2009/एचएसएल/डी(एसवाई) का पीसी-II दिनांक 23.03.2011 PC-II to 8(2)/2009/HSL/D(SY) Dated 23.03.2011	37222.00	#
	<b>जोड़ TOTAL</b>			<b>109222.00</b>	

- # ब्याज देयता के बिना शाश्वत कर्ज।  
# Loan in perpetuity without any interest liability.  
- कॉलम 7 में कर्ज की वृद्धि को ‘-’ चिह्न के साथ दर्शाया गया है।  
- In column No. 7 increase in Loans has been shown with ‘-’ Sign.  
\* प्रतिकूल शेष राशियों के सुधार के लिए रेल मंत्रालय के संबंध में पूर्व अवधि समायोजन (पीपीए) को दर्शाता है।  
\* PPAs on account of Ministry of Railways to rectify Adverse Balances.

**वित्त लेखे, संघ सरकार**  
**FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT**  
**भारत सरकार लेखा मानक: 3**  
**INDIAN GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD: 3**  
**सं.3 – संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिम राशियों का विवरण**  
**No. 3 – STATEMENT OF LOANS AND ADVANCES MADE BY THE UNION GOVERNMENT**  
**भाग: 2 ऋणों और अग्रिम राशियों का सारांश : सेक्टरवार**  
**Section: 2 Summary of Loans and Advances: Sector-wise**

सेक्टर	01 अप्रैल, 2020 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्अदायगी	अप्रतिसंहरणीय कर्जों और अग्रिम राशियों को बट्टे खाते डालना	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (2-6)	बकायों में ब्याज अदायगी
Sector	Balance on April 1, 2020	Disbursements during the year	Repayments during the year	Write-off of irrecoverable loans and advances	Balance on March 31, 2021 (2+3)-(4+5)	Net increase/ decrease during the year (2-6)	Interest payment in arrears
1	2	3	4	5	6	7	8
							(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
सामान्य सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6075) General Services— (Major Head 6075)	—	—	—	—	—	—	—
सामाजिक सेवाएं (6202 से 6250 तक मुख्य शीर्ष) Social Services	8841865.55	699174.00	135488.06	—	9405551.49	—563685.94	113920.44
(Major Heads from 6202 to 6250)							
आर्थिक सेवाएं (6401 से 7475 तक मुख्य शीर्ष और मुख्य शीर्ष 7615) Economic Services	5482791.86	9336443.19	1204609.29	—	13614625.76	—8131833.90	3690618.81
(Major Heads from 6401 to 7475 and Major Head 7615)							
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार (मुख्य शीर्ष 7601 & 7602) State and U.T. Governments (Major Head 7601 & 7602)	18081417.24	14880393.36	1610699.21	—	31351111.39	—13269694.15	426123.41

विदेश सरकारें (मुख्य शीर्ष 7605) Foreign Governments (Major Head 7605)	1422777.49	53915.11	31072.42	—	1445620.18	—22842.69	—
सरकारी कर्मचारी (मुख्य शीर्ष 7610) Government Servants (Major Head 7610)	18282.94 *0.03	14628.85	10447.52	—	22464.30	—4181.33	—
<b>जोड़ TOTAL</b>	<b>33847135.08</b> <b>0.03</b>	<b>24984554.51</b>	<b>2992316.50</b>	<b>—</b>	<b>55839373.12</b>	<b>—21992238.01</b>	<b>4230662.66</b>

**नोट:** विवरण के लिए संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिम राशियों के विस्तृत विवरण के भाग 1 (विवरण सं. 15) को देखें।

**Note:** For details, refer Section 1 of Detailed Statement of loans and advances made by the Union Government (Statement no. 15).

- कॉलम 7 में कर्ज की वृद्धि को '-' चिह्न के साथ दर्शाया गया है।

- In Column No. 7 increase in Loans has been shown with '-' Sign.

\* प्रतिकूल शेष राशियों के सुधार के लिए रेल मंत्रालय के संबंध में पूर्व अवधि समायोजन (पीपीए) को दर्शाता है।

\* PPAs on account of Ministry of Railways to rectify Adverse Balances.

वित्त लेखे, संघ सरकार  
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

भारत सरकार लेखा मानक: 3

INDIAN GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD: 3

सं.3- संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिम राशियों का विवरण

No.3 - STATEMENT OF LOANS AND ADVANCES MADE BY THE UNION GOVERNMENT

भाग: 3 राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से और अन्य ऋणी संस्था से बकाया में पुनर्दायगी का सारांश

Section: 3 Summary of repayments in arrear from State or Union Territory Governments and other Loanee entities

ऋणी संस्था Loanee Entity	31 मार्च, 2021 को बकाया राशि Amount of arrears as on March, 31, 2021			प्रारंभिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है Earliest period to which arrears relate	31 मार्च, 2021 को संस्था के विरुद्ध बकाया कुल कर्ज Total loans outstanding against the entity on March 31, 2021	
	1	2	3			4
		प्रधान Principal	ब्याज Interest	कुल Total		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें State/Union Territory Governments		330255.29	426123.41	756378.70	1984-85	31351111.39
अन्य ऋणी संस्थाएं Other Loanee entities		1815370.53	3804539.25	5619909.78	1957-58	1835222.21
<b>जोड़ TOTAL</b>		<b>2145625.82</b>	<b>4230662.66</b>	<b>6376288.48</b>		<b>33186333.60</b>

नोट: विवरणों के लिए, संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिमों के विस्तृत विवरण (विवरण सं.15) के भाग 2 एवं 3 को देखें।

Note: For details, refer Section 2 & 3 of Detailed Statement of loans and advances made by the Union Government (Statement no. 15).